

नवभारत

संस्थापक : स्व. रामगोपाल माहेश्वरी | प्रेरणा स्रोत : स्व. प्रफुल्ल माहेश्वरी

गुजरात के नर्मदा जिले में एक पुल के गिरने की ताजा घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या भारत अपने बुनियादी ढांचे को लेकर वास्तव में गंभीर है? इस हादसे में कई वाहन नदी में समा गए और दर्जनों लोगों की जान चली गई. इससे पहले जून 2024 में बिहार के सहरसा, मधेपुरा और सुपौल जिलों में तीन सप्ताह के भीतर चार पुल गिर चुके थे. उस समय राज्य सरकार ने इसे 'प्राकृतिक आपदा' और 'जल-प्रवाह की तीव्रता' से जोड़ा था, लेकिन क्या यह तर्कसंगत है?

बिहार के कटिहार जिले में गंगा पर बना 263 करोड़ रुपये का पुल उद्घाटन से पहले ही ढह गया था. झारखंड के साहिबगंज में गंगा पर बन रहा पुल तीन बार गिर चुका है, और उसकी लागत अब तक 2000 करोड़ रुपये पार कर चुकी है. पश्चिम बंगाल के बहरामपुर में 2023 में पुल ढहने से सारत लोगों की जान गई थी. मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में 2024 की

लापरवाही की भेंट चढ़ते निर्माण कार्य

बारिश में तीन पुलों पर आवाजाही रोकनी पड़ी क्योंकि निर्माण के एक साल के भीतर ही दरारें आने लगी थीं. उतराखंड में 2023 में चारधाम यात्रा के दौरान 9 जगह सड़कें धंस गईं, जबकि उन पर हाल ही में करोड़ों का निर्माण हुआ था. यह समस्या सिर्फ तकनीकी नहीं है. यह शासन व्यवस्था, संस्थागत जवाबदेही और राजनैतिक इच्छाशक्ति की असफलता है. सड़कों, पुलों और भवनों के निर्माण में भ्रष्टाचार एक स्वीकृत परंपरा बन चुका है. ठेकेदारों को राजनीतिक संरक्षण मिलता है. अधिकारियों की लापरवाही पर आंखें मूंद ली जाती हैं, और जांचें केवल औपचारिकता बनकर रह जाती हैं.

आजादी के पहले बने ब्रिज आज भी सक्रिय हैं—जैसे मुंबई का 'कैनेडी ब्रिज' या कोलकाता का 'हावड़ा ब्रिज'—जबकि हाल में

बने कई पुल उद्घाटन से पहले ही गिर रहे हैं. भारत सरकार ने 2023 में 'नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन' और 'गति शक्ति योजना' जैसी योजनाएं घोषित की थीं, जिनका उन पर हाल ही में करोड़ों का निर्माण हुआ था. लेकिन जमीनी स्तर पर निगरानी और क्रियान्वयन की स्थिति यह है कि करोड़ों के बजट के बाद भी बुनियादी ढांचा 'अस्थायी' बना हुआ है.

नितिन गडकरी जैसे वरिष्ठ मंत्री खुद स्वीकार कर चुके हैं कि कई परियोजनाओं में गुणवत्ता से समझौता हुआ है. लेकिन जब तक दौषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं होती, तब तक यह स्वीकारोक्ति भी जनता की पीड़ा पर मराम नहीं बन सकती. दरअसल इसे रोकने के लिए जरूरी है कि राष्ट्रीय निर्माण गुणवत्ता

आयोग जैसा स्वतंत्र निगरानी निकाय गठित किया जाए. प्रत्येक निर्माण परियोजना की 'डिजिटल ट्रेकिंग' और 'पब्लिक ऑडिट रिपोर्ट' उपलब्ध कराई जाए. दोषी पाए गए ठेकेदारों और इंजीनियरों को ब्लैकलिस्ट और दंडित किया जाए. निर्माण कंपनियों को पांच साल की गारंटी और वार्षिक निरीक्षण दायित्व सौंपा जाए. कुल मिलाकर हमारे नेताओं की घोषणाओं में 'इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रांति' की बातें हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आज भी एक पुल बना जितना कठिन नहीं, उतना उसे टिकाए रखना हो गया है. अगर हर पुल गिरने के बाद मुआवजे और जांच से आगे कुछ नहीं होता, तो फिर हम किस 'विकसित भारत' की नींव रख रहे हैं? क्योंकि जब बुनियादी ही भरोसेमंद नहीं, तो इमारत चाहे जितनी ऊंची हो—वह ढह ही जाएगी. जाहिर है सरकारी पैसों से बनाए जा रहे निर्माण लापरवाही और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते जा रहे हैं.

महाकौशल की डायरी

महाकौशल में बदलेंगे सियासी समीकरण



अविनाश दीक्षित

सर्वविदित है कि राजनीति में प्रत्येक घटनाक्रम के अलग मायने होते हैं, जिनका मतलब और असर भी जुदा होता है. किसी की नियुक्ति अथवा विदाई को



ग्राामीण क्षेत्र के एक वरिष्ठ और चर्चित विधायक की अलग तरीके से चल रही है. ऐसे में

लेकर भी कयासबाजियों का दौर शुरू हो जाता है. मौजूदा सूरते हाल में भगवा दल में नए प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के पार्टी ध्वज संभालते ही महाकौशल में नए समीकरण पर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है.

कुछ दिन पहले तक भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रहे विष्णु दत्त शर्मा की लॉबी का संगठन में बोलबाला रहा किंतु अब नए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के नए समर्थक सामने आने लगे हैं. भाजपा में संगठन सर्वोपरि माना जाता है, लिहाजा नेतृत्वकर्ता चेहरा कोई भी रहे, संगठन की आंतरिक गतिविधियों पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता. मगर इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि नेतृत्व में बदलाव के साथ ही सांगठनिक समीकरणों पर सतही मैन्यूफैक्चरिंग पर जोर खासतौर पर स्वागत योग्य है. जैसे-जैसे वैश्विक मूल्य श्रृंखलाएं नए सिरे से बदल रही हैं, भारत भी कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, उपभोक्ता वस्तुओं और फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में एक विश्वसनीय विकल्प के रूप में तेजी से उभर रहा है. इन क्षेत्रों में दीर्घकालिक रोजगार सृजन का समर्थन करके, ईएलआई योजना पीएलआई योजनाओं, 'मेक इन इंडिया' तथा 'स्किल इंडिया' जैसी मौजूदा पहलों का पूरक बनने के साथ-साथ शहरी व अर्द्ध-शहरी, दोनों समूहों में औद्योगिक विकास को गति देगी.

अक्सर लागत संबंधी चिंताओं के कारण औपचारिक भर्ती को बढ़ाने में बाधाओं का सामना करने वाले सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को यह योजना महत्वपूर्ण राहत प्रदान करती है. नियोक्ता-पक्ष के प्रोत्साहन नई भर्ती की सीमांत लागत को कम करते हैं. इससे विस्तार, औपचारिकीकरण और श्रमशक्ति के उन्नयन की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है. वैश्विक स्तर पर, वेतन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं रोजगार को बढ़ावा देने में कारगर साबित हुई हैं. जर्मनी जैसे देश अप्रेंटिसशिप और दीर्घकालिक भर्ती के लिए नियोक्ता सक्विडी प्रदान करते हैं.

अफसरों के जाल में उलझी मंत्री

मंडला से विधायक और प्रदेश की पीएचडी मंत्री संपतिया उर्दकें द्वारा 1000 करोड़ कमीशन लेने का मामला इन दिनों खासी सुर्खियां बटोर रहा है. बीते सप्ताह यह विषय कैबिनेट बैठक में भी उठा. चर्चा है कि अधिकारियों को बाहर करने के बाद मुख्यमंत्री ने अन्य मंत्रियों से कहा कि मंत्री की शिकायत का विषय उनके पास आना चाहिए था, फिर सीधे शिकायत नीचे कैसे चली गई...? उन्होंने आश्चर्यपूर्ण भाव से कहा कि ऐसी शिकायतें जिन्हें एंटरटेन ही नहीं किया जाना चाहिए उन शिकायतों पर कागज कैसे चल जाते हैं...? कुछ ऐसे ही सवाल अन्य मंत्रियों ने उठाए और कहा कि मंत्री के अधीनस्थ अधिकारी मंत्री के खिलाफ आई शिकायत की जांच कैसे कर सकता है...? खबर है की ईएनसी को सिविल सेवा आचरण का उल्लंघन करने पर नॉटिस जारी कर दिया गया है. फिलहाल पूर्व विधायक किशोर समरीते द्वारा की गई शिकायत और उस पर चली कागजी कार्रवाई से माहौल गरमाया है. चर्चाएं अनेक तरह की हो रही हैं, कुछ लोग शिकायत को सही नहीं मान रहे हैं, तो कुछ किशोर समरीते की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रहे हैं. जबकि कुछ लोगों का कहना है कि शिकायत का अंजाम कुछ भी हो लेकिन यह तो स्पष्ट हो ही गया है कि एक मंत्री को उसके अधीनस्थ अधिकारी ही उलझा सकते हैं तो फिर आम जनों के प्रति अफसरों का रवैया कैसा रहता होगा, इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है.

रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना एक उत्प्रेरक



ज्योति विज

महानिदेशक, फिक्की

यह एक बेहद ही सामयिक और सोचा-समझा कदम है. लगभग एक लाख करोड़ रुपये के परिव्यय वाली यह योजना भारत के

उभरते रोजगार परिदृश्य, विशेषकर मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र, में एक साहसिक नीतिगत हस्तक्षेप है. अगले दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों के सृजन को समर्थन देने के उद्देश्य से तैयार की गई यह ईएलआई योजना महज एक आर्थिक उपाय भर नहीं है - यह भारत की श्रमशक्ति के भविष्य में एक ऐसा रणनीतिक निवेश है, जो सीधे तौर पर सरकार के विकसित भारत2047 के विजन का समर्थन करता है. ईएलआई देश में रोजगार सृजन का एक प्रमुख उत्प्रेरक बनने जा रहा है.

कई अन्य ऐसे देशों के उलट, जहां आबादी शीघ्र ही घटने लगेगी या घट चुकी है, भारत में अभी भी कार्यशील आयु वर्ग की एक ऐसी बड़ी आबादी है, जिसे रोजगार के

ईएलआई योजना भारत की रोजगार नीति की परिपक्वता - अल्पकालिक राहत से हटकर दीर्घकालिक श्रम बाजार के विकास की दिशा में बदलाव - को दर्शाती है. ढलती उम्र वाली आबादी के साथ-साथ डिजिटल और हरित बदलावों जैसे व्यापक वैश्विक रुझानों की पृष्ठभूमि में, ऐसी कारगर नीतियां अधिक संख्या में लोगों को गुणवत्तापूर्ण नौकरियां सुलभ कराने की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं. फिक्की में, हम अपने सदस्यों से इस योजना का सदुपयोग करने हेतु आगे आने का आग्रह करते हैं. नियोक्ताओं- खासकर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) से जुड़े- को इसे वित्तीय लाभ से कहीं आगे बढ़कर देखना चाहिए. यह योजना परिचालन को बढ़ाने, युवा प्रतिभाओं का दोहन करने, वेतन भुगतान प्रणाली (पेरोल) का औपचारिकीकरण करने और स्थायी आर्थिक मूल्य सृजित करने का एक उपकरण है. उद्योग जगत के एक शीर्ष चैंबर के रूप में, फिक्की इस उद्देश्य का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है.

अधिक अवसरों की जरूरत है. ईएलआई योजना का उद्देश्य नौकरी चाहने वालों और नौकरी देने वालों के बीच ही नहीं बल्कि इससे भी अधिक महत्वपूर्ण रूप से अनौपचारिक कार्य एवं औपचारिक रोजगार के बीच की खाई को पाटना है.

रोजगार संबंधी तात्कालिक नतीजों से परे जाकर, इस बात पर गौर करना महत्वपूर्ण है कि ईएलआई योजना विभिन्न सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की दिशा में भारत की प्रगति को मजबूत करती है. खासतौर पर, औपचारिक व दीर्घकालिक रोजगार को प्रोत्साहित करके एसडीजी 8 (समृद्धि) तथा आर्थिक विकास) और कम वेतन पाने वालों एवं पहली बार नौकरी चाहने वालों को लक्षित वित्तीय सहायता प्रदान करके

एसडीजी 1 (गरीबी उन्मूलन) तथा एसडीजी 10 (असमानताओं में कमी) के संदर्भ में.

आधार-समर्थ प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्रणाली (डीबीटी सिस्टम) के जरिए ईपीएफओ पंजीकरण एवं संचितकरण के साथ इस योजना का जुड़ाव न केवल रोजगार सृजन बल्कि सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार भी सुनिश्चित करता है, जोकि एक न्यायसंगत और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है. भारत द्वारा किए गए ऐसे प्रयासों को मान्यता देते हुए, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) ने हाल ही में भारत की इस उपलब्धि को स्वीकार किया और आधिकारिक तौर पर अपने डैशबोर्ड पर इस तथ्य को प्रकाशित किया कि भारत की 64.3 प्रतिशत आबादी

(2015 में 19 प्रतिशत की तुलना में), यानी 94 करोड़ से अधिक लोग अब कम से कम एक सामाजिक सुरक्षा लाभ के दायरे में हैं. मैन्यूफैक्चरिंग पर जोर खासतौर पर स्वागत योग्य है. जैसे-जैसे वैश्विक मूल्य श्रृंखलाएं नए सिरे से बदल रही हैं, भारत भी कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, उपभोक्ता वस्तुओं और फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में एक विश्वसनीय विकल्प के रूप में तेजी से उभर रहा है. इन क्षेत्रों में दीर्घकालिक रोजगार सृजन का समर्थन करके, ईएलआई योजना पीएलआई योजनाओं, 'मेक इन इंडिया' तथा 'स्किल इंडिया' जैसी मौजूदा पहलों का पूरक बनने के साथ-साथ शहरी व अर्द्ध-शहरी, दोनों समूहों में औद्योगिक विकास को गति देगी.

अक्सर लागत संबंधी चिंताओं के कारण औपचारिक भर्ती को बढ़ाने में बाधाओं का सामना करने वाले सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को यह योजना महत्वपूर्ण राहत प्रदान करती है. नियोक्ता-पक्ष के प्रोत्साहन नई भर्ती की सीमांत लागत को कम करते हैं. इससे विस्तार, औपचारिकीकरण और श्रमशक्ति के उन्नयन की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है. वैश्विक स्तर पर, वेतन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं रोजगार को बढ़ावा देने में कारगर साबित हुई हैं. जर्मनी जैसे देश अप्रेंटिसशिप और दीर्घकालिक भर्ती के लिए नियोक्ता सक्विडी प्रदान करते हैं.

दुर्लभ खनिज में आत्मनिर्भर होगा देश

चीन द्वारा दुर्लभ खनिज (रेयर अर्थ एलिमेंट) के निर्यात पर रोक लगाए जाने से कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवी वाहनों, एडवांस एनर्जी सिस्टम, रक्षा क्षेत्र के मिसाइल व डार, रिन्यूएबल एनर्जी आदि क्षेत्रों में चिंता व्याप्त हो गई थी. इसके बावजूद भारत के लिए इस क्षेत्र में अवसर है. विश्व के कुल दुर्लभ खनिज का 8 प्रतिशत हिस्सा भारत में है. अब केंद्र सरकार का उपक्रम इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड (आईआरईएल) ऐसे दुर्लभ खनिजों के निर्यात में कटौती करने तथा इनकी देश में ही प्रक्रिया (प्रोसेसिंग) बढ़ाने की दिशा में सक्रिय होगा. इस समय विश्व में दुर्लभ खनिज के खनन व प्रक्रिया में चीन ही अग्रणी है जबकि भारत का इसके खनन में सिर्फ 1 प्रतिशत योगदान है. अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार 2030 तक दुर्लभ खनिज के खनन में चीन की हिस्सेदारी 69 P.श. से घटकर 51 प्रतिशत रह जाएगी तथा रिफाइनिंग भी 90 फीसदी से घटकर 76 प्रतिशत हो जाएगी. इसकी वजह

यह है कि विश्व में अधिक संतुलित व नियमित सप्लाई चैन विकसित करने के प्रयास होने लगे हैं. मेगनेट की कमी से ईवी का निर्माण प्रभावित हो सकता है, इसलिए सरकार नेशनल क्रिटिकल मिनेरल मिशन (एनसीएमएम) शुरू करने जा रही है ताकि इस क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बन सके. देश को वलीन एनर्जी टेक्नोलॉजी, ऑटोमोटिव सेक्टर तथा हाईटेक रक्षा प्रणालियों के लिए दुर्लभ खनिज की आवश्यकता है. विदेश से सप्लाई में देरी से होनेवाले व्यवधान से बचने तथा लागत वाजिब रखने के उद्देश्य से स्वदेश में दुर्लभखनिज का खनन और प्रोसेसिंग बढ़ाना आवश्यक हो गया है. इस क्षेत्र में निवेश बढ़ाना, अंतरराष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देना तथा परमिट देने की प्रक्रिया का सरलीकरण जरूरी है. भारत के तमिलनाडु, केरल, आंध्रप्रदेश व ओडिशा के समुद्र तटीय क्षेत्रों में दुर्लभ खनिज का भंडार है. ऐसे 130 भंडार या डिपॉजिट की पहचान कर ली गई है.



दुर्लभखनिज का खनन और प्रोसेसिंग बढ़ाना आवश्यक हो गया है. इस क्षेत्र में निवेश बढ़ाना, अंतरराष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देना तथा परमिट देने की प्रक्रिया का सरलीकरण जरूरी है. भारत के तमिलनाडु, केरल, आंध्रप्रदेश व ओडिशा के समुद्र तटीय क्षेत्रों में दुर्लभ खनिज का भंडार है. ऐसे 130 भंडार या डिपॉजिट की पहचान कर ली गई है.

संपादकीय बोर्ड | प्रबंध संपादक : सुमीत माहेश्वरी, समूह संपादक : क्रांति चतुर्वेदी

शब्द-सागर : डॉ. सागर खादीवाला

CROSS WORD 11959 - डॉ. सागर खादीवाला

1	2	3	4	5
	6	7		
8	9	10		11
12	13		14	
	15		16	
17		18		19
	20	21		22
23		24		

बाएं से दाएं

- हजार से संबंध रखनेवाला, शाही जमाने का एक ओहदा (उर्दू)
- मदद, सहायता, साथ मिलकर कार्य करना (सं.)
- गहरी और युक्तियुक्त बात
- सामान, असबाब, बहुमूल्य वस्तु
- जोर से भिड़ना
- पैर के नाखून से लेकर सिर तक के सब अंग
- अभाव, कमी
- संत विनोदाभावे के साथ इस स्थान का नाम जुड़ा है
- चिद्री, पत्नी, पाती
- असंतोष या विरोध आदि प्रकट करने के लिए कल-कारखानों बाजारों तथा दुकानों आदि का बंद होना
- उत्तर, मुकाबले की चीज, नौकरी से हटाने की आज्ञा (उर्दू)
- मुसलमानों का मजहबी त्यौहार
- मान-चित्र, भवन आदि का रेखाचित्र
- ओर, बगल, पक्ष (उर्दू)

Solution 11958

1	अ	क	2	3	4	5
अ	क	क	अ	अ	अ	अ
8	9	10		11		
9	अ	अ	10	अ	अ	अ
11	अ	अ	12	अ	अ	अ
13	अ	14	अ	15	अ	अ
अ	अ	16	17	18	अ	अ
अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ
19	अ	अ	अ	अ	अ	अ
अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ

ज्योतिषाचार्य प्रियंका नारायणशंकर व्यास, कोतवाली बाजार, जबलपुर (म.प्र.)

आज जिनका जन्मदिन है

वर्ष के प्रारंभ में नई योजनाओं का शुभारंभ होगा, सांसारिक सुखों की वृद्धि होगी, वर्ष के मध्य में पारिवारिक सुख अच्छा रहेगा, व्यापार व्यवसाय में सुधार होगा, वर्ष के मध्य में पारिवारिक सुख अच्छा रहेगा, व्यापार में सुधार होगा, वर्ष के अन्त में उतावलीपन में लिये गये निर्णय से हानि होगी, शत्रु पक्ष प्रबल रहेगा, अत्याधिक परिश्रम से मन व्यथित रहेगा.

को शत्रु पक्ष प्रबल रहेगा, वृष और तुला राशि के व्यक्तियों को अत्याधिक परिश्रम से मन दुखी होगा, कर्क और सिंह राशि के व्यक्तियों को उतावलेपन में लिये गये निर्णय में सुधार होगा, धनु और मीन राशि के व्यक्तियों को कार्यों में वृद्धि होगी, मकर और कुंभ राशि के व्यक्तियों को पारिवारिक जीवन में सफलता मिलेगी, मिथुन और कन्या राशि के व्यक्तियों को सावधानी पूर्वक कार्यों में लगना होगा.

आज जन्म शिशु का भविष्य

आज जन्म लिया बालक स्वस्थ, सुन्दर, हंसमुख, मिलनसार होगा. शिक्षा में अग्रणी होगा. नौकरी या पेशेविक कार्यों में संलग्नता रहेगी. मेहनत अधिक करेगा. माता पिता का भक्त होगा.

उदयकालीन ग्रह हाल

रा.मि. 20 संवत् 2082 श्रावण कृष्ण प्रतिपदा भृगुवासे रात 2/0, पूर्वाषाढा नक्षत्र प्रातः 6/34, वैधृति योगे रात 10/9, बालव करणे सू.उ. 5/16 सू.अ. 6/44, चन्द्र चार धनु दिन 12/46 से मकर, शु. रा. 10, 12, 1, 4, 5, 8 अ.रा. 11, 2, 3, 6, 7, 9 शुभांक- 3, 5, 9.

व्यापार भविष्य

श्रावण कृष्ण प्रतिपदा को पूर्वाषाढा नक्षत्र के प्रभाव से लाल रंग की वस्तुओं में तेजी होगी, किन्तु आज मंदा पर गेहूँ, चना में तेजी का रूख रहेगा. तिलहन में तेजी का योग है. सफेद रंग की वस्तुओं में अचानक तेजी होगी. भाग्यांक 5719 है.

मेघ- अपनी मेहनत को बेकार होने देना खिन्नता पैदा करेगा. प्रियजनों से मनमुटाव संभव है. किसी व्यक्ति को सहायक आपक कार्यों को गति देना. लाभप्रद सूचना मिलेगी.

वृषभ- भावनाओं में बहकर आप परिवार को विरोधी बना लेंगे, जोखिम के कार्यों में रुचि बढेगी. किसी व्यक्ति के द्वारा अपमान का शिकार होना पड़ेगा.

मिथुन- अपनी बात समझाने में नाकाम परेशानी दूर होगी. आर्थिक लाभ का योग है. कामकाजी महिलाओं को कार्य अधिक करना होगा.

सिंह- कार्य का चिन्तन तनाव का कारण बन सकता है. व्यापारिक सौदेबाजी में सावधानी रखें. कुतूहलियों के कार्यों को पूरा करने में व्यस्तता रहेगी.

कन्या- योजनाओं में बदलाव करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं. दुविधा से हटकर कार्य करें. पूँजी लगाने में सावधानी रखें. मांगलिक कार्य बनेंगे. संयम रहेगा.

तुला- अपूर्ण समाचारों पर लिये गये फैसले से नुकसान होगा. स्वयं से कोई भूल होगी. विलासिता की वस्तुओं का संयच होगा. सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा.

वृश्चिक- सुख सुविधा के सामानों पर बड़े खर्च की संभावना है. दीक्षुप में सफलता मिलेगी. सुख सुविधा को आनन्द की अनुभूति होगी. कुछ कार्यों में परेशानी आ सकती है.

धनु- प्रापटी संबंधी विवादों के समाधान से राहत मिलेगी. कोर्ट कचहरी के कार्यों में विलंब होगा. सुख शांति में कमी होगी. कम लाभ में भी संतोष बना रहेगा.

मकर- आपका शुकाव परिवार की ओर कुछ ज्यादा ही रहेगा, जिससे कार्य स्थल की व्यवस्था बिगड़ सकती है. कार्य कुशलता से बड़े बड़े काम बनेंगे.

कुम्भ- मांगलिक कार्यों में खर्च को संभालना बन सकती है. व्यापार व्यवसाय में सावधानी रखें. सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी. जीवनशैली के सहयोग से लाभ होगा.

मीन- तनाव के चलते सेहत बिगड़ सकती है. शुभ समाचारों के मिलने का योग है. परिश्रम साध्य होगा. नौकरी में अधिकारियों के कोप का सामना करना पड़ेगा.

SUDOKU 7091

		5		3				
2			9	5				
9					6			
	6					3	5	
4	8						7	
		7						3
			2	4				9
		8				2		

प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं. इनका क्रमवार होना आवश्यक नहीं है. आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 333 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें. पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते. पहले का केवल एक ही हल है.

नवभारत सूटोके 7090

4	2	5	8	6	1	9	7	3
7	3	1	9	4	2	8	5	6
6	9	8	7	3	5	4	2	1
1	6	2	3	8	9	5	4	7
9	4	3	5	1	7	6	8	2
8	5	7	4	2	6	3	1	9
2	1	9	6	5	8	7	3	4
5	7	4	1	9	3	2	6	8
3	8	6	2	7	4	1	9	5